(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (घ) सरकार ने पटसन क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने तथा नीतियों तथा नीतिपरक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी ताकि उसका आधुनिकीकरण, विविधीकरण किया जा सके तथा निर्यात में वृद्धि की जा सके। इस संपति में नवंबर, 1992 में सरकार को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों में विशेष महत्व इस बात पर दिया गया है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य विविधीकृत अंत प्रयोगों में एक फाइबर के रूप में पटसन की पूर्ण संभाव्यता को मान्यता प्रदान करने में निहित है। ऐसे विविधीकरण से यार्न और फैब्रिक जैसे मध्यवर्ती कच्चे माल का उत्पादन करके पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। जिसका उपयोग विविधीकृत उपयोगों के लिए ठोस उत्पादों के उत्पादन करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा जिससे रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पाद के लिए अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी क्योंकि पटसन फाइबर की मांग में पुनः वृद्धि होगी। समिति ने मार्जिन धनराशि सहायता तथा सभी संबद्ध क्षेत्रों के साथ जैसे उत्पादकता में सुधार तथा कच्चे पटसन की गुणवत्ताओं सुधार, उद्यमियों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच एक और पारस्परिक संबंध स्थापित करके तथा दूसरी और प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए वित्तीय संस्थानों ओर विपणन माध्यमों के बीच संबंध स्थापित करके उपयुक्त व्यवस्था करके विविधीकरण को सहायता देने की सिफारिश की है। सरकार ने अधिकांश सिफारिशों पर पहले से ही कार्रवाई कर ली है।

हथकरघा उद्योग

5390. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हथकरघा उद्योग पर निर्भर है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार हथकरघा उद्योग के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों की वित्तीय स्थिति और खराब हो गयी है;

(ग) हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये क्या-क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1987-88 में की गई हथकरघों से संबंधित गणना के अनुसार कुल 156.1 लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग पर निर्भर थे जो उस समय की जनसंख्या के 2% के बराबर था। उसके बाद अब तक कोई गणना नहीं की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं इनमें निम्नलिखित योजनाऐं शामिल हैं:—

1. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।
2. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना।
3. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।
4. कार्यशाला-सह-आवास योजना
5. थ्रिफ्ट फंड योजना।
6. समूह बीमा योजना।
7. जनता कपड़ा योजना।
8. विपणन विकास सहायता योजना।
9. राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह प्रोग्राम।
10. राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना।

इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान लगभग 30 लाख बुनकरों को शामिल करने के लिए 3000 हथकरघा विकास केन्द्रों और 500 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की एक योजना भी आरम्भ की है।

हथकरघा बुनकरों को सूती धागे और सूती धागे की आपूर्ति

5391. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सूती धागे और सूती धागे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ग) हथकरघा बुनकरों की मुख्य समस्या सूत के बढ़ते हुए मूल्य हैं न कि सूत का उपलब्ध न होना। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने हथकरघा बुनकरों को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. हथकरघा क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में हैंक यार्न की उपलब्धता बनाएं रखने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा हैंक यार्न बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विदेश व्यापार के महा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सूत के निर्यातकों को सूत निर्यात करने से पूर्व हैंक यार्न बाध्यता की शर्तों को पूरा करना होता है।

2. नई कताई मिलों की स्थापना, वर्तमान मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए और साथ ही हथकरघा क्षेत्र में सूत उपलब्ध कराने के लिए मार्जिन मनी देते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता देने में विस्तार।

3. हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना को 20 मिलियन किलोग्राम सूत की डिलिवरी के लक्ष्य और सब्सिडी की दर 20 रु॰ प्रति किलोग्राम बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में जारी रखना।

4. विभिन्न राज्य सरकारों को 20 मिलियन किलोग्राम के बढ़ते हुए लक्ष्य के साथ मिल गेट मूल्यों पर राष्ट्रीय हरकरघा विकास निगम के माध्यम से हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए मिल गेट मूल्य योजना को जारी रखना।

5. समूचे देश में हथकरघा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य शीर्ष हथकरघा संघों के माध्यम से 100 सूत डिपो और 20 मोबाइल वैन आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

वस्त्र उद्योग के रुग्ण एककों का आधुनिकीकरण

5392. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र उद्योग के रुग्ण एककों का आधुनिकीकरण करने के लिये और इस प्रक्रिया में कामगारों को सम्मिलित करके इन एककों में सहयोग का वातावरण पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्षों में इस दिशा में क्या-क्या प्रयास किए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (ग) टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों ने 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 2005.72 करोड़ रु॰ के निवेश पर एक योजना तैयार की है। आधुनिकीकरण योजना अन्य बातों के साथ-साथ 36 गैर-अर्धक्षम मिलों का 18 अर्धक्षम मिलों में पुनर्संरचना के बारे में परिकल्पना की गई है। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ इसकी अधिग्रहित मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्धक्षम बनाया जा सकता है।

वस्त्र उद्योगों पर वस्त्र नीति का प्रभाव

5393. **श्री आस मोहम्मद:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस तथ्य की जांच कर रही है कि वस्त्र नीति का रुग्ण वस्त्र उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार वस्त्र नीति की वर्तमान संरचना के आधार पर वस्त्र नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।